



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252910
CG-DL-E-13032024-252910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 59]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(राष्ट्रीय महिला कोष)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सं. 19/3/2023-निदेशक(आरएमके) कार्यालय.—जबकि, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 1993 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) के तहत दिनांक 31.03.1993 को 31 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना की गई थी। आरएमके को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका प्रयोजन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आजीविका गतिविधियों, आवास, सूक्ष्म उद्यमों और पारिवारिक जरूरतों के लिए ग्राहक-हितैषी, बिना गिरवी के और परेशानी रहित तरीके से सूक्ष्म वित्तपोषण उपलब्ध कराना था। दिसंबर 2001 में व्यय वित्त समिति की मंजूरी के साथ आरएमके के कोष को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया। आरएमके ने ऋण, निवेश और वसूली प्रबंधन द्वारा आंतरिक स्रोतों से उत्पन्न धन के माध्यम से अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना व्यय को पूरा किया।

जबकि, आरएमके निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करता है:

- गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों, राज्य सरकार की एजेंसियों और महिला सहकारी बैंकों इत्यादि जैसे मध्यवर्ती सूक्ष्म-वित्तपोषण संगठनों (आईएमओ) के माध्यम से महिला सूक्ष्म-उद्यमियों सहित महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को सूक्ष्म ऋण प्रदान कराना।
- आईएमओ को 6% पर उधार देता है और आईएमओ एसएचजी को अधिकतम 10% ब्याज दर पर उधार दे सकता है।

- iii. वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, उद्यम विकास और कौशल उन्नयन में एसएचजी और भागीदार संगठनों का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण करता है।

जबकि, नवंबर, 2020 में भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार (पीआईए) द्वारा सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर तैयार की गई रिपोर्ट में आरएमके को बंद करने की सिफारिश की गई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार और सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत बैंकों से ऋण की आसान उपलब्धता के कारण इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। इसके अलावा, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी स्कीमों ने लाखों स्वयं सहायता समूहों की ऋण संबंधी जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वे विशाल बैंकिंग नेटवर्क और सस्ते ऋण का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, पीएम मुद्रा योजना ने वंचित आबादी के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ, बैंक रियायती, बिना गिरवी सूक्ष्म ऋण प्रदान करने में सफल रहे हैं।

जबकि, मंत्रिमंडल की दिनांक 06.04.2023 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यवाई की है:-

- (i) आरएमके के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (एसवीआरएस) के तहत दिनांक 31.12.2023 से विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है।
- (ii) आरएमके की अधिशेष निधियां (कॉर्पस और रिजर्व और सरप्लस निधि) भारत की संचित निधि ("सीएफआई") को वापस कर दी गई हैं।
- (iii) आरएमके का बकाया ऋण पोर्टफोलियो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो विकासात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला वित्तीय संस्थान है और अनिवार्य क्षेत्रों में बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के 'जैसा है जहां है' के आधार पर ऋण प्रवाह को बढ़ाता है।

जबकि, आरएमके के विघटन/बंद करने के जो प्रस्ताव आरएमके की आम सभा द्वारा अपनी 62वीं और 63वीं बैठकों ("जीबीएम") में पारित किए गए थे, उन्हें दिनांक 18.06.2022 को आयोजित आरएमके की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदित कर दिया गया।

उपरोक्त के मद्देनजर, आरएमके के सभी प्रचालन और गतिविधियां दिनांक 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दी गई हैं।

रजिस्ट्रार (फर्म एवं सोसायटी)/एस.डी.एम.(मुख्यालय), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली ने पत्र सं. आरओएस/एसडीएम(मुख्यालय)/2024/75 दिनांक 19.02.2024 द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 के तहत आरएमके के विघटन को रिकॉर्ड में ले लिए जाने की सूचना दी है।

आरएमके के कर्मचारियों को दिए गए एसवीआरएस, आरएमके के बकाया ऋण पोर्टफोलियो को सिडबी को हस्तांतरित करने, सभी खातों को बंद करने और इसके विघटन के मद्देनजर दिनांक 19 फरवरी 2024 से इस सोसायटी का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

रजनीश मोहन सिंह, निदेशक

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(Rashtriya Mahila Kosh)

New Delhi, the 1st March, 2024

No. 19/3/2023-O/o Director(RMK).—Whereas, Rashtriya Mahila Kosh (RMK) was set up by the Government of India in 1993 under the then Ministry of Human Resource Development (Department of Women & Child Development) with an initial corpus of Rs.31 crores by the Government of India on 31.03.1993 for the purpose of providing micro-loans to women through Government & Non-Government Organisations. RMK was registered as a society under the Societies Registration Act, 1860, with the purpose of extending micro-finance in a client-friendly, without-collateral, and hassle-free manner for livelihood activities, housing, micro-enterprises, and family needs to

bring about socio-economic upliftment of the women. The corpus of RMK was enhanced to Rs.100 crores with the approval of Expenditure Finance Committee in December 2001. RMK met all its administrative and establishment expenditures through funds generated from internal sources via credit, investment and recovery management.

Whereas, the RMK performs the following activities:

- i. provides micro-credit to women Self-help Groups (SHGs)/Joint Liability Groups (JLGs) including women micro-entrepreneurs through Intermediary Micro-financing Organizations (IMOs) like NGOs, Cooperative Societies, State Government Agencies, and Women Cooperative Banks etc.
- ii. lends to IMOs at 6% and IMOs can lend to SHGs at a maximum interest rate of 10%.
- iii. undertakes skill up gradation and capacity building of SHGs and partner organizations in financial management, project management, enterprise development, and skill up-gradation.

Whereas, the report on rationalization of government bodies prepared by Principal Economic Adviser (PrEA) to the Government of India in November, 2020 on Rationalization of Govt. Bodies recommended to close down the RMK as it has lost relevance due to the expansion of financial services in rural areas and easy availability of credit from banks under various schemes of the government. Further, schemes like the Deendayal Antodaya yojana-National Rural Livelihood Mission, Deendayal Antodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission have successfully nurtured lakhs of self Help Groups, who can access the vast banking network and cheap credit. Additionally, PM Mudra Yojna has played a key role in enhancing credit availability to the uncovered population. Over a period of time, banks have been successful providing concessional, collateral free micro credit.

Whereas, in compliance of the decision taken by the Cabinet in its meeting held on 06.04.2023, Ministry has taken the following actions:-

- (i) The employees of RMK have been given Special Voluntary Retirement under Special Voluntary Retirement Scheme(SVRS) w.e.f. 31.12.2023
- (ii) Surplus funds of RMK(Corpus and Reserves & Surplus Funds) have been returned to the Consolidated Fund of India("CFI").
- (iii) The outstanding loan portfolio of RMK has been transferred to Small Industries Development Bank of India (SIDBI), a Financial Institution that focuses on developmental aspects line enhanced credit flow to the mandated segments, on 'as is where is basis' without any monetary consideration.

Whereas, the resolutions for dissolution/closure of RMK that were passed by the RMK's General Body at its 62nd and 63rd General Body Meetings ("GBMs"), was approved in 27th Annual General Meeting (AGM) of RMK held on 18.06.2022.

In view of the above, all operations and activities of RMK stands closed w.e.f. 31st December, 2023.

Registrar (Firms & Societies)/S.D.M(HQ), M.B. Road, Saket, New Delhi vide communication no. ROS/SDM(HQ)/2024/75 dated 19.02.2024 conveyed that the dissolution of RMK under Section 13 of the Societies Registration Act, 1860, has been taken on record.

In view of the SVRS given to the employees of RMK, transfer of outstanding loan portfolio of RMK to SIDBI, closure of all accounts and its dissolution, the Society ceased to exist w.e.f. 19th February, 2024.

Issues with the approval of the Competent Authority in the Ministry of Women and Child Development, Government of India

RAJNEESH MOHAN SINGH, Director